LOK SABHA

Tuesday, July 23, 1968/Sravana 1, 1890 (SAKA)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBER SWORN

SHRI BINDHESHWARI PRASAD MANDAL (Madhipura—Bihar):

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Royalty payment on coal and iron ore to Bihar

*31. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the National Development Council meeting held in New Delhi in May, 1968, the Chief Minister of Bihar urged upon the Central Government for an increase in the payment of royalty on coal and iron ore to Bihar;

(b) if so, the response of Government to it; and

(c) the royalty presently paid to Bihar vis-a-vis the Bihar's percentage of the total minerals available in the country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) and (b). The question raised in the meeting was of a general nature. The rates of royalty on major minerals, with the exception of coal and iron ore, have recently been revised. The revision of royalty on coal and iron ore in still under consideration.

(c) The royalty earning of Bihar during 1966 was Rs, 5,33,35,165. The important minerals produced in Bihar represent varying percentages of the total production in the country. However, Bihar accounted for thirtyseven percent in total value of major minerals produced in India during 1967 against thirty-eight percent during 1966.

श्री शिव चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय कदम कदम पर बिहार की घोर उपेक्षा हो रही है । आप जानते हैं कि बिहार हिन्दुस्तान में वह राज्य है, जिस में कुदरत की दौलत है, जिस की मिट्टी में जाफरान है और जिस के पास जन-शक्ति है । इस के बावजूद केन्द्रीय सरकार के निकम्मेपन और उस की उपेक्षा की वजह से आज बिहार पिछड़ा हुआ और अविकसित रखा गया है । बिहार के खनिज पदार्थ वहां पर इस्तेमाल न हो कर बाहर जाते हैं—हिन्दुस्तान के बाहर भी जाते हैं । बिहार की जनता को इस से फायदा नहीं हो रहा है । वहां पर जो कुछ भी उद्योग हैं, वे मोटे तौर पर बिहार के कोने में हैं । औद्योगीकरण की दृष्टि से सारा बिहार पिछड़ा हुआ और अविकसित है । कोयला और लोहा अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है और बिहार उन का भंडार है । उन का भी फायदा सारी जनता को नहीं हो रहा है । इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि परसेंटेज की टर्म्स में और एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना कोयला और लोहा बिहार में मिलता है, उस में से कितना बिहार में इस्तेमाल होता है, कितना बिहार से बाहर हिन्दुस्तान के दूसरे भागों में होता है और कितना हिन्दुस्तान से बाहर होता है ।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जहां तक रायल्टी से आमदनी का ताल्लुक है, बिहार स्टेट की आमदनी सब स्टेट्स से ज्यादा है। मिनरल्ज की रायल्टी को बढ़ाने के सम्बन्ध में बिहार और अन्य स्टेट्स की मांग को ध्यान में रखते हुए उस रायल्टी को बढ़ाया गया है। बिहार में पैदा होने वाले खनिज पदार्थ दूसरी स्टेट्स में कितने इस्तेमाल होते हैं, इस का ब्रेकअप देना इस वक्त मुश्किल है। यह सम्भव भी नहीं है कि एक स्टेट में पैदा होने वाले खनिज पदार्थ उसी स्टेट में इस्तेमाल हों और वे दूसरी जगह न भेजे जायें। यही सोच कर अगर सारे कोयले का इस्तेमाल केवल बिहार में किया जायेगा, तो सारे हिन्दुस्तान का क्या होगा ?

श्री शिव चन्द्र झा : बिहार के खनिज पदार्थों का इस्तेमाल केवल बिहार में न हो बल्कि सारे हिन्दुस्तान में हो, इस भावना को सामने रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि कोयले और लोह की खानों के मालिकों को प्रति-वर्ष उनसे कितना मुनाफा होता है–कितना ग्रास और नेट प्राफिट होता है। उस मुनाफे का फायदा सारे देश को हो, इस उद्देश्य से क्या सरकार कोयले और लोहे की खानों का राष्ट्रीयकरण करने जा ही है, अगर हां, तो कब; यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, 6,79 लाख टन कोयले के उत्पादन में से 3,13 लाख टन का उत्पादन इस समय बिहार में होता है। फिलहाल कोयले की खानों के राष्ट्रीयकरण का कोई सुझाव सरकार के समक्ष नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा : क्यों नहीं है ? सरकार इस मामले की जड़ में क्यों नहीं जाती है ? यह मुनाफाखोरी का साथ दे रही है।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: For the last many years, the various State Governments have asked for a revision of the royalty rates for the different ores. May I know whether Government have taken any decision to allow the State Governments to increase the royalty rates on iron ore or manganese ore or different other ores?

SHRI P. C. SETHI: Royalty rates in the matter of many ores except coal and iron ore have been increased. The question of royalty rates with regard to coal and iron ore is still under consideration. Recently, the Coal Advisory Council has taken a decision that even with respect to coal, the royalty rates should be on the tonnage basis. Now, the question of increasing the royalty is still under consideration.

SHRI R. K. AMIN: In view of the fact that coal and crude oil are very close associates, and the question of royalty on both is connected together, may I have an assurance from the hon. Minister that when the reconsideration of the question of royalty on coal is taken up, the reconsideration of the question of royalty on the crude oil will also be taken up?

SHRI P. C. SETHI: As far as the question of royalty on crude oil is concerned, I am sorry I would not be in a position to say anything. With regard to the royalty on coal, certainly we shall take into consideration the overall picture and the decision of the Srinagar meeting of the Ministers that there should not be violent disturbances in the rates of royalty.

श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या यह सही है कि मई में होने वाली एन० डी० सी० की मीटिंग से पहले भी कई बार बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बात का आग्रह किया था कि उस की गरीबी को देखते हुए उस के मिनरल्ज की रायल्टी को बढ़ाने के लिए

कोई बड़ी कमेटी बनाई जाये या उस प्रश्न पर फिर विचार किया जाये ?

श्री प्र० चं० सेठी : रायल्टी के प्रश्न पर विचार करने के लिए डीकास्टा कमेटी बनाई गई थी । उस की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार किया गया है और स्टेट्स की मांग को देखते हुए रायल्टी रेट्स को बढ़ा दिया गया है । सेक्शन 9(3) के अनुसार वर्तमान रायल्टी रेट्स में 20 परसेंट से ज्यादा इज़ाफ़ा नहीं हो सकता है । डीकास्टा कमेटी की सिफारिश है कि 20 परसेंट वाले सेक्शन को हटा दिया जाये । सरकार इस पर विचार कर रही है ।

खुले माल डिब्बों में ले जाया जाने वाले गेहूं को क्षति

+

*32. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ओंकार सिंह :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री देवेन सेन :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री कं० हाल्दर :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत के खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को भेजा जाने वाला गेहूं वर्षा के कारण खराब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(ग) इस हानि के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों तथा अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त गेहूं के लिए भारतीय खाद्य निगम ने बन्द माल डिब्बे मांगे थे जबकि उसको खुले माल डिब्बे दिये गये थे;

(ङ) क्या यह भी सच है कि वर्षा से गेहूं को बचाने के लिए कुछ खुले माल डिब्बों को तिरपाल से भी नहीं ढका गया था ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI PARIMAL GHOSH): (a) A small portion of the wheat transported by rail in recent months to stations in West Bengal by the Food Corporation of India was damaged due to rain.

(b) About 900 tonnes.

(c) None was held responsible.

(d) The Food Corporation had agreed to utilise covered as well as open wagons for the movement of wheat from Punjab and Haryana in order to maximize despatches before the monsoons. As such, open wagons were supplied to a limited extent against requisition for covered wagons.

(e) Some of the wagons loaded during dry weather were not covered with tarpaulins.

(f) Considering the huge quantities to be moved, some use of open wagons was inevitable. Acute labour shortage at several destination points, however, held up unloading and the turn-round of wagons and tarpaulins was, therefore, seriously